डी.आर.डी.ओ. के मानवरहित डिमॉन्स्ट्रेटर विमान की पहली उड़ान सफल रही

इसे ऑटोमैटिक विमान टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में डी.आर.डी.ओ. और भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है

अनमैन्ड एयरपक्राफ्ट आने वाले समय में वॉर और डिफैन्स की पहली सीढ़ी माने जा रहे हैं। शुक्रवार को डी.आर.डी.ओ. निर्मित पूर्णतः स्वदेशी अनमैन्ड (मानवरहित) डिमॉन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान पूरी तरह से सफल रही। इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ने पूरी तरह ऑटोमैटिक मोड में उड़ान भरते हुए टेक-ऑफ, वे पॉइंट नैविगेशन आदि का शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से टचडाउन भी किया। इसे रक्षा क्षेत्र में भारत और डी.आर.डी.ओ. की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उत्कृष्ट योगदान के लिए डी.आर.डी.ओ. को बधाई दी है।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। डिफैंस रिसर्च एण्ड डवलपमैंट ऑर्गनाइजेशन (डी.आर.डी.ओ.) उपलब्धियों में शुक्रवार को एक और नाम जुड़ गया। डी.आर.डी.ओ.ने शुक्रवार को ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टैक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर अर्थात मानवरहित विमान की पहली उड़ान का कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस विमान ने पूरी तरह ऑटोमैटिक मोड में उड़ान भरते हुए टेक-ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन आदि का शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से टचडाउन भी किया।

इस विमान की यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में जरूरी तकनीक को साबित करती है। इसके साथ ही स्ट्रैटिजिक डिफेंस टेक्नॉलजी की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम है। इस मानव रहित विमान को बेंगलुरु के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने डिजाइन और डिवेलप किया है। कर्नाटक की ए.डी.ई., डी.आर.डी.ओ. की एक प्रमुख रिसर्च लैबोरेट्री है। यह विमान एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा ऑपरेट होता है।

- इस विमान ने पूरी तरह ऑटोमैटिक मोड में उड़ान भरते हुए टेक-ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन आदि का शानदार प्रदर्शन किया और आसानी से टचडाउन भी किया।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डी.आर.डी.ओ. को बधाई दी और कहा कि, यह कदम भारत की रक्षा क्षेत्र में और मजबूती बढ़ायेगा।

खास बात यह है कि इस विमान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह मिलिट्री टेक्नालॉजी की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डी.आर.डी.ओ. के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने इस प्रणाली के डिजाइन, विकास और परीक्षण से जुड़ी टीमों के प्रयासों की सराहना की।

बड़ी खबर कन्हैयालाल के हत्यारों ने खोले कई खौफनाक राज, एक और हत्या का था प्लान!

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डी.आर.डी.ओ. को बधाई देते हुए कहा कि, यह ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे महत्वपूर्ण मिलिट्री सिस्टम्स के रूप में 'आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यह हमारी सैन्य प्रौद्योगिकी की उन्नति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मानिर्भर भारत के सपने को पूरा करता है।

हत्यारे हाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रियाज अजमेर ल ाया गया। यहां उन्हें जेल के अन्दर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में अलग-अलग गहन बैरकों में रखा गया है।

राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को मिल गया अकाली दल का साथ

शिरोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने एन.डी.ए. को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने की घोषणा की

नई दिल्ली, 1 जुलाई। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल अब राष्ट्रपति चुनाव में एक-दूसरे के साथ आ गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को कहा कि, वह राष्ट्रपति चुनाव में नैशनल डैमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा। गौरतलब है कि, किसान कानून के पास होने तक शिरोमणि अकाली दल भी एन.डी.ए. के हिस्से के तौर पर बीजेपी का सहयोगी था। पंजाब विधानसभा चुनावों में अभी 4 महीने पहले एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही थीं। उन चुनावों में दोनों पार्टियों को कोई खास सफलता नहीं मिली थी।

भाजपा के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मुर्मू के समर्थन के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से बात की थी, जिसके एक दिन बाद पार्टी ने यह फैसला किया। अकाली दल ने कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। इन कानूनों को केंद्र की मोदी सरकार ने वापस ले लिया था।

- पंजाब विधानसभा चुनावों में अभी 4 महीने पहले ही दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। उन चुनावों में दोनों पार्टियों को कोई खास सफलता नहीं मिली थी।

बादल ने कहा, 'हमने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला किया है।'

कृषि कानूनों और सिख कैदियों की रिहाई के मुद्दों का हवाला देते हुए बादल ने कहा कि उनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ कई मतभेद हैं, लेकिन अकाली दल ने हमेशा समाज के गरीब व कमजोर वर्ग के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, यह मुद्दा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला का है और उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है।'

सुखबीर बादल ने कहा, 'अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए, हमने सही रास्ता चुनने का फैसला किया है।

अकाली दल का इतिहास बताता है कि उसने हमेशा गरीबों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। कोर कमेटी की बैठक में लगभग 3 घंटे तक विचार करने के बाद हमने सर्वसम्मति से फैसला किया कि हम मुर्मू का समर्थन करेंगे।'

शर्म...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हममें से उस प्रत्येक व्यक्ति के प्रण को मजबूत किया है, जो इन विध्वंसात्मक विभाजनकारी विचारधाराओं से लड़ रहा है।"

जयराम ने आगे कहा कि "राजनीतिक लाभ के लिए देश को अव्यवस्था में धकेलने वाली और किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी ताकतों के ध्रुवीकरण के विरूद्ध अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी लड़ाई कभी खत्म नहीं करेगी और सभी भारतीय उनके उद्दण्डात्मक कार्यों का मुकाबला करें।"

कांग्रेस के अधिकारिक ट्विटर हैण्डिल ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भाजपा सरकार के चेहरे पर एक तमाचे की संज्ञा दी।

कोर्ट द्वारा नुपूर शर्मा से क्षमा मांगने की बात कहने पर कांग्रेस ने प्रश्न किया कि, क्या भाजपा अध्यक्ष, केन्द्रीय गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को निरंतर साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के लिए देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए।"

नूपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वापस लेने के लिए याचिका

सामाजिक कार्यकता अजय गौतम ने कहा है कि, कोर्ट की ऐसी टिप्पणी से नूपुर शर्मा की जान को खतरा और बढ़ गया है

नई दिल्ली, 1 जुलाई। सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें गौतम ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा के लिए की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है। सी.जे.आई. को भेजी याचिका में कहा गया है कि इससे नूपुर को जान का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि नूपुर शर्मा को टीवी पर देश से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उदयपुर की घटना के लिए भी उनका बयान ही जिम्मेदार है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिसमें मांग की गई कि उनके खिलाफ दर्ज केस देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज हैं। क्योंकि उनकी जान को खतरा है इसलिए उनका केस दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसे पहले हाई कोर्ट में दायर किया जाना था।

अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि नूपुर शर्मा केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को वापस लिया जाना चाहिए।

- गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा मामले में टिप्पणी की है कि, देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के लिए नूपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है उन्हें टी.वी. पर आकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिये।

याचिका में इसके पीछे तर्क दिया गया है कि इससे नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। उन्हें फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए।

"रियल" शिव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकता था। उस वक्त शिवसेना अधिकारिक रूप से आपके साथ थी। यह सी.एम. शिवसेना का सी.एम. नहीं है। जब शिवसेना वहां है ही नहीं तो शिवसेना का सी.एम. कैसे हो सकता है।" शिंदे सरकार के पहले निर्णय पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि "मेरा गुस्सा मुम्बईवासियों पर मत निकालिए।

मैट्रो शैड का प्रस्ताव मत बदलिए। मुम्बई के पर्यावरण के साथे खिलवाड़ मत कीजिए। यदि आप मुझ पर गुस्सा हैं तो मुझे चोट पहुंचाएं, मुम्बई और पर्यावरण को नहीं। कांजुरमार्ग पर मैट्रो 3 कारशैड के प्रस्ताव पर विचार करें। आरे में कारशैड बनाने पर जोर ना दें।"

सूत्रों ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, दोनों ने शिंदे से वादा किया है कि उन्हें शिवसेना की विरासत संभलवाने का हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। तथापि, विशेषज्ञों का कहना था कि यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का केस मजबूत है।

जहां यह बात सही है कि, शिवसेना के विधायी भाग में शिंदे को बढ़त प्राप्त है, क्योंकि पार्टी के दो तिहाई विधायक उनके साथ हैं, लेकिन पार्टी के अधिकारिक सदस्य बहुत भारी संख्या में ठाकरे के साथ हैं और पार्टी संगठन पर उनका पूर्ण नियंत्रण है।

भाजपा, चार माह बाद होने जा रहे बृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बी.एम.सी.) के चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है और इस प्रतिष्ठित निकाय पर, जिसका बजट करोड़ों में हैं, शिवसेना का दबदबा खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रही है।

यह एक मजबूत कारण था कि, भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और देवेन्द्र फड़नविस को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए बाध्य किया।

भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह भली भांति जानता है कि, जब तक बी.एम.सी. पर उद्धव ठाकरे का नियन्त्रण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मुम्बई पर उसका नियन्त्रण स्थापित नहीं हो सकता। उद्धव, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए हमेशा से आंख की किरकिरी रहे हैं, खासतौर से मोदी और शाह के लिए, किन्तु ठाकरे के नेतृत्व वाली एम.वी.ए. सरकार के ढाई वर्ष के शासनकाल में ठाकरे तथा मोदी-शाह के बीच शत्रुता और गहरी ही हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, और जो भी शिवसेना का वास्तविक सुप्रीमो बनकर उभरेगा वो इसे दिशा देगा।

18 बीमा यूनियन्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की

नई दिल्ली, 1 जुलाई (वार्ता)। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 18 ट्रेड यूनियनों और संघों के संयुक्त फोरम ने कहा है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है तथा बीमा क्षेत्र के 50 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य कर रही है।

बीमा कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे उत्तरी क्षेत्र के संयोजक त्रिलोक सिंह ने बताया कि गुरुवार को इस संबंध में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया गया और सरकार यदि मांग नहीं मानती है तो 11 जुलाई से बीमा क्षेत्र के 50 हजार से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

- बीमा कर्मियों की ट्रेड यूनियन्स का दावा है कि, इस हड़ताल में 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा लेंगे।

कर्मचारी नेता ने कहा कि 30 जून को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी संघों के सभी घटकों की 11 जुलाई को फिर बैठक होगी जिसमें स्थिति की समीक्षा कर आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बीमा क्षेत्र की कंपनियों में लगभग 58000 कर्मचारी और अधिकारी हैं। कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में मुख्य प्रबंध निदेशकों के कार्यालयों के समक्ष छह जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस,नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल बीमा कंपनी सहित सभी इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हिस्सा लेंगे।

छोटी पार्टियों को उनकी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और बिहार में क्षेत्रीय दलों के कंधों पर सवारी करने वाली भगवा पार्टी की यात्रा सफल रही। इन दोनों ही राज्यों में भाजपा बड़ी सहयोगी है। दूसरी और इस संबंध में कांग्रेस का अनुभव निराशाजनक रहा है।

उसके सहयोगियों की शक्ति में जहां इज़ाफा हुआ है, वहीं कांग्रेस स्वयं हाशिए पर आने की स्थिति का उत्तरोत्तर सामना करती रही है। भाजपा ने जहाँ राज्य में अपना संगठनात्मक ढांचा मज़बूत करने के विचार से गठबन्धर किए हैं वहीं, कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करने के विचार के साथ ही प्राय: गठबन्धन करती आयी है। मतदान विशेषज्ञ डैनियल फ्रांसिस के अनुसार "कांग्रेस की इन रणनीतियों का उल्टा असर हुआ है।"

देश की पहली फ्लोटिंग सोलर पैनल परियोजना शुरु हुई

नई दिल्ली, 1 जुलाई (वार्ता)। देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन पूरी तरह से शुरू हो गया है।

एन.टी.पी.सी. ने तेलंगाना के रामागुंडम में एक जुलाई मध्यरात्रि से 100 मेगावाट तैरती सौर पीवी परियोजना में से 20 मेगावाट क्षमता के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। इसी के साथ ही रामागुंडम में 100 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया।

उर्जा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना उन्नत तकनीक के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल विशेषताओं से सम्पन्न है। मेसर्स भेल के माध्यम से ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण) अनुबंध के रूप में 423 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। यह परियोजना 40 खंडों में विभाजित हैं और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक खंड में एक तैरता प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सरणी होती है। तैरते प्लेटफॉर्म में एक इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर और एक एच.टी. ब्रेकर होता है। सौर मॉड्यूल एच.डी.पी.ई. (उच्च घनत्व पॉलीथीन) सामग्री से निर्मित फ्लोटर्स पर रखे जाते है।

- तमिलनाडु के रामागुंडम के एक जलाशय के 500 एकड़ क्षेत्र में इस 100 मेगावॉट की सोलर परियोजना का संचालन किया जा रहा है
- यह परियोजना 40 खण्डों में विभाजित है और इनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.5 मेगावाट है। प्रत्येक खण्ड में एक तैरता प्लेटफॉर्म और 11,200 सौर मॉड्यूल की एक सारणी होती है।

उन्होंने बताया कि तैरते रहने वाली इस पूरी प्रणाली (फ्लोटिंग सिस्टम) को विशेष एच.एम.पी.ई. (हाई मॉड्यूलस पॉलीइथाइलीन) रस्सी के माध्यम से संतुलित जलाशय क्षेत्र (बैलेंसिंग रिजरवायर बेड) में रखे गए कुल भार तक लंगर डाला जा रहा है।

'नूपुर शर्मा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डिबेट में देखा कि, वे कितनी उत्तेजित थीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह सब कहा और बाद में यह भी कहा कि वो एक वकील हैं, बहुत लज्ज़ाजनक है। ......उन्हें टी.वी. पर जाना चाहिये था तथा देश से माफी माँगनी चाहिये थी।"

27 मई को टी.वी. पर हुई उक्त बहस वाराणसी-स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के विषय पर थी। उस टी.वी. डिबेट की कड़ी आचोलना करते हुये, न्यायमूर्ति कांत ने पूछा, उस टी.वी. चैनल ने न्यायालय में विचाराधीन विषय चुना ही क्यों था। जब बैंच को यह बताया गया कि, नूपुर शर्मा ने अपनी टिप्पणी एंकर के प्रश्न के जवाब में की थी, तो जज ने कहा कि, ऐसी स्थिति में होस्ट (बहस का आयोजक टी.वी. चैनल) के खिलाफ भी मुकदमा दायर होना चाहिये था।

नूपुर शर्मा के सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुँचने के संदर्भ में बोलते हुये, जज ने कहा: "याचिका से भी उनके अहंकार की गंध आ रही है कि, देश के मजिस्ट्रेट उनके आगे बहुत तुच्छ हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "जब आप अन्य लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दायर करते हैं तो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जब एफ.आई.आर. आपके खिलाफ है तो किसी में आपको छूने तक की हिम्मत नहीं है।"

उन्होंने कहा कि, जब मुम्बई पुलिस 17 जून को उनसे पूछताछ करने दिल्ली आई तो पुलिस को वे नहीं मिल सकीं क्योंकि वे गायब हो गई थीं और इस सब के बाद, वे अदालत से यह राहत चाहती हैं कि सभी एफ.आई.आर. जोड़ दी जायें।

'राज्यों का केन्द्र पर 75 हजार करोड़ रु. से ज्यादा का राजस्व बकाया हो चुका है'

कांग्रेस ने कहा है कि, जी.एस.टी के अविकसित और अस्पष्ट स्वरूप के कारण केन्द्र व राज्यों के बीच मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं

नई दिल्ली, 1 जुलाई (वार्ता)। कांग्रेस ने कहा है कि वस्तु एवं सेवाकर-जी.एस.टी. से पिछले पांच साल में अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची है और सरकार को इस पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इसको सरल बनाने के लिए संसद में इस पर विस्तार से चर्चा करानी चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम तथा पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज सरकार जी.एस.टी. के पांच साल पूरे होने का जश्न मना रही है लेकिन इस नई प्रणाली की खामियों के वजहों से इन पांच सालों में देश को नफे की बजाय भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. से केंद्र तथा राज्यों के बीच परस्पर विश्वास कम हुआ है और राज्यों का केंद्र पर 75 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व बकाया हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. से देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योग-एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की इकाइयां बर्बाद हो रही हैं। इकाइयों के बंद होने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गये हैं।

चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह का जी.एस.टी. लागू किया है उसमें जो नियम बनाए गये हैं उनके कारण कोई भी राज्य जी.एस.टी. संग्रह का काम अच्छी तरह नहीं कर पा रहा है। इसके नियम टेढ़े हैं जबकि उन्हें सरल होना चाहिए। केंद्र को इस कर प्रणाली को लागू करते समय राज्यों को सहूलियत को भी देखना चाहिए लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया है।

कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कहा कि जी.एस.टी. अधूरा है और यही वजह है कि इसके नियमों में बराबर सुधार करने की जरूरत पड़ रही है। आधे अधूरे ढंग से तैयार जी.एस.टी. के नियमों के कारण लोगों की दिक्कतें बढ रही है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। देश में बड़ी संख्या में एम.एस.एम.ई. में काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. को सरल बनाने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और संसद में इस पर चर्चा करवाकर इसमें बुनियादी बदलाव किये जाने की जरूरत है। उनका कहना था कि जी.एस.टी. में सही सुधार तब ही हो सकता है जब सभी दलों को इस पर चर्चा के लिए सरकार बुलाए। यदि सरकार जी.एस.टी. पर सर्वदलीय बैठक करती है तो देश को एक सही और सटीक जी.एस.टी. मिल सकता है।

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं जयराम रमेश और पी. चिदम्बरम ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, जी.एस.टी. में रही खामियों एवं सुधार के लिए इस पर संसद में चर्चा कराये जाने की आवश्यकता है।
- जयराम रमेश ने कहा कि, केन्द्र सरकार जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के पांच साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन जब तक इसकी खामियां दूर नहीं होती यह जश्न अधूरा है।

भारत में आजादी के बाद अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सबसे बड़े सुधार के तहत लम्बी चर्चाओं के बाद एक जुलाई 2017 को जी.एस.टी. लागू किया गया था और जी.एस.टी. अधिनियम के तहत केंद्रीय वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वाधिकार संपन्न जी.एस.टी. परिषद गठित की गई है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को स्थान दिया गया है और परिषद के अब तक के प्राय: सभी निर्णय सर्व सम्मति से हुए हैं। चिदम्बरम और रमेश ने कहा कि मोदी सरकार ने आज के दिन पांच साल पहले जिस जी.एस.टी. को लागू किया था वह पूर्ववर्ती सरकार की सिफारिशों वाला जी.एस.टी. नहीं था। पांच साल में जी.एस.टी. अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में पूरी तरह से बेअसर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रणाली से केवल बड़ी कंपनियों, चार्टर्ड एकाउंटेंटों तथा जी.एस.टी. वकीलों को ही फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. के कारण सबसे ज्यादा नुकसान एम.एस.एम.ई. को ही हुआ है। कांग्रेस नेताओं यह भी याद दिलाया कि उनके नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने जिस जी.एस.टी. लागू करने का प्रस्ताव किया था उसका उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपना रुख बदल दिया और जी.एस.टी. को सबसे अच्छी कर प्रणाली बताते हुए आधी संसद बुलाकर इसे लागू कर दिया।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने जो जी.एस.टी. प्रणाली दी है उसमें स्थिरता का अभाव है। पिछले पांच साल में जी.एस.टी. परिषद ने जो काम किया है उसमें पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय का वर्चस्व रहा है और वहां से जो फरमान आता वही लागू होता रहा है। जी.एस.टी. परिषद में राज्यों की सुनवाई नहीं होती है और उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। जी.एस.टी. के तहत राजस्व क्षति पूर्ति व्यवस्था को और आगे तक बढाए जाने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन जी.एस.टी. परिषद की हाल की बैठक में इस मुद्दे पर विचार तक नहीं किया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जी.एस.टी. लागू करते समय राज्यों को राजस्व में एक न्यूनतम स्तर से कम की वृद्धि होने पर क्षतिपूर्ति करने की कानूनी गारंटी प्रदान की थी। यह गारंटी पांच साल के लिए की थी और इसकी अवधि जून 2022 में पूरी हो गई। इसके लिए विशेष जी.एस.टी. उपकर लागू करने की व्यवस्था की गई है।

इसाईयों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में शारीरिक बर्बरता एवं चर्चों को बंद किये जाने के मामले सामने आये हैं।

राष्ट्रपति पद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णय लेने से पहले, विपक्ष के साथ विचार-विमर्श किया होता तो विपक्ष ने भाजपा के इस चयन (मुर्मू) का निश्चित रूप से समर्थन किया होता क्योंकि वे आदिवासी होने के साथ ही, महिला भी हैं। ऐसा लगता है, मानो ममता के लिये आदिवासी तथा महिला-दोनों के संयोग से बेहतर संयोग कोई और है ही नहीं। लेकिन, जैसी राजनेता वो हैं, चुनावी गणित उनकी समझ में जल्दी और आसानी से आ जाता है तथा उन्होंने चुनावी गणित के हिसाब से ही अपनी प्रतिक्रिया दी है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908